

आर्थिक शक्तिलता और क्षतपूरति

चर्चा में क्यों

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) हेतु क्रेडिट उपलब्धता में सुधार करने के लिये सरकार द्वारा किया जा रहा हस्तक्षेप स्वागत योग्य कदम है जो आर्थिक संवृद्धि में सहायक साबित हो सकता है। यह एक स्वीकार्य तथ्य है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSMEs) वमिद्रीकरण (Demonetisation) के साथ-साथ वस्तु एवं सेवा कर (GST) जैसे कानूनों से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- वमिद्रीकरण (Demonetisation) ने इन इकाइयों के समक्ष मजदूरों को नकद भुगतान और क्रेडिट हासिल करने की समस्या खड़ी कर दी, जो अनौपचारिक चैनलों के माध्यम से बड़े पैमाने पर होता था।
- इसी तरह वस्तु एवं सेवा कर (GST) ने कागजी काम-काज से मुक्त, नकदी में व्यवसाय करने के नहिती फायदों से वंचित करते हुए अनुपालन लागत में वृद्धि कर दी।
- तथ्य यह है कि MSMEs का बकाया सकल बैंक क्रेडिट वास्तव में सितंबर 2014 और सितंबर 2018 के बीच 4.71 लाख करोड़ रुपए से घटकर 4.69 करोड़ रुपए हो गया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जैसे पुनर्वित्त योजनाओं के बावजूद औपचारिक ऋण संस्थान आर्थिक शक्तिलता को गति देने में असमर्थ रहे हैं।
- यह चिंताजनक इसलिए है क्योंकि MSME क्षेत्र देश के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 30 प्रतिशत, वनिरमाण उत्पादन का 45 प्रतिशत और व्यापार नरियात का 40 प्रतिशत हिस्सा धारण करता है।
- यह देखते हुए कि GST और वमिद्रीकरण जैसे कानूनों की मार झेलते हुए भी MSME क्षेत्र ने बैंकिंग प्रणाली की गैर-नष्पिपादति परसिंपत्तियों के संकट में सबसे कम योगदान किया है, अतः सरकार की नैतिक ज़िम्मेदारी बनती है कि इस क्षेत्र की सहायता की जाए।
- हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को लोन की सुविधा प्रदान की गई है। इससे हफ्तों बैंकों के चक्कर लगाने, बोझिल व जटिल पेपरवर्क करने की कोई जरूरत नहीं होगी।
- केंद्र सरकार ने एक वेबसाइट भी लॉन्च की है जिससे 1 करोड़ रुपए तक के बज़िनेस लोन सरिफ 59 मिनट में मलि जाएंगे।
- छोटे उद्यमियों के लिये यह योजना काफी कारगर साबित होने वाली है और इसके तहत 20-25 दिनों की बजाय सरिफ 59 मिनट में लोन को मंजूरी मलि जाएगी। मंजूरी के बाद करीब एक हफ्ते में लोन का वतिरण हो जाएगा।
- इस सरकारी वेबसाइट पर एक घंटे से भी कम वक्त में 10 लाख से लेकर एक करोड़ रुपए तक के बज़िनेस लोन को सैद्धांतिक मंजूरी मलि चुकी है।
- गैर-बैंकिंग वत्ति कंपनियों (NBFCs) की स्थिति भी चिंता का वषिय है, जनिंका MSMEs में कुल औपचारिक क्रेडिट हिस्सा दसिंबर 2015 में करीब 5.5 प्रतिशत की तुलना में मार्च 2018 में 10 प्रतिशत हो गया है।
- ऐसे संस्थान अब खुद लक्विडिटी की कमी का सामना कर रहे हैं, जैसे IL&FS का ऋण न चुका पाना।

शक्तिल पड़ती जा रही अर्थव्यवस्था के वभिनिन क्षेत्रों को गतिप्रदान करने वाले ऐसे उपाय स्वागत योग्य हैं। इसके अलावा सतत आर्थिक संवृद्धि के लिये सामरिक उपायों को भी अपनाने की आवश्यकता है जो अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में आपसी सामंजस्य बैठाते हुए गतिप्रदान करने में सक्षम होंगे।